

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में अनुकरणीय प्रयासों के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए।
- प्रधानमंत्री ने आज प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया।
- द्वीप समूह में भी विश्व दिव्यांग दिवस दो हजार पच्चीस पर दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- अस्मिता खेलो इंडिया वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप में द्वीप समूह की महिला वेटलिफ्टर्स ने बाज़ी मारी— जीते दो मेडल।

<><><><><><><><>

आज नौसेना दिवस है। भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिका के सम्मान में प्रत्येक वर्ष चार दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर सभी भारतीय नौसेना कर्मियों, पूर्व नौसैनिकों तथा उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं।

प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने आज नौसेना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय नौसेना कर्मियों के शौर्य और बलिदान को नमन किया। भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिका को सम्मान देने के लिए हर साल नौसेना दिवस मनाया जाता है। उन्नीस सौ इकहत्तर में इसी दिन ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान भारतीय नौसेना ने पीएनएस खैबर सहित चार पाकिस्तानी जहाजों को डुबो दिया था।

<><><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर सभी वन्यजीव प्रेमियों और चीतों की रक्षा के लिए समर्पित संरक्षणवादियों को शुभकामनाएं दीं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने चीते को धरती के सबसे महत्वपूर्ण वन्यजीवों में से एक बताया और तीन साल पहले शुरू किए गए प्रोजेक्ट चीता की सफलता को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चीता पर्यटन की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर खुशी हो रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वन्यजीवों की रक्षा और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना भारत के सभ्यतागत लोकाचार का अभिन्न अंग है और आज भी इन प्रयासों में यही भावना देखी जा सकती है।

<><><><><><><><>

केंद्र सरकार ने "धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान" के तहत देश भर के जनजातीय गाँवों के विकास के लिए अस्सी हजार करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में, जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य तिरसठ हजार से ज़्यादा गाँवों में बुनियादी ढाँचे की कमी को पूरा करना है जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली की पहुँच में सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए इतनी बड़ी धनराशि आवंटित की है। श्री ओराम ने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समुदाय के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन और "धरती आबा" लागू कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम जनमन कार्यक्रम का उद्देश्य पचहत्तर विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों को शामिल करना है और चौवन हजार से ज़्यादा घरों का निर्माण किया जा रहा है।

<><><><><><><><>

सांसद बिष्णु पद रे ने प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री से द्वीप समूह में सरकारी नौकरियों हेतु अधिकतम आयु सीमा चालीस वर्ष निर्धारित करने का अनुरोध किया है। सांसद ने कहा है कि प्रशासन के अन्तर्गत ग्रुप-बी के अराजपत्रित तथा ग्रुप-सी पदों पर भर्ती के लिये अधिकतम आयु सीमा चालीस वर्ष निर्धारित की जाए तथा स्थानीय उम्मीदवारों को अतिरिक्त पांच वर्ष की छूट प्रदान की जाए, जैसा कि हाल ही में लदाख के लिये जारी आदेश में किया गया है। सांसद ने बताया कि प्रशासन अब भी पुरुष के लिये अट्ठारह से तैंतीस और महिलाओं के लिए अट्ठारह से अड़तीस वर्ष आयु वर्ग को जारी रखे हुए है, जिसके कारण कई पात्र युवा नौकरी के अवसरों से वंचित हो रहे हैं। श्री रे ने कहा कि अनेक राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशों में अधिकतम आयु सीमा चालीस से बयालीस वर्ष के दायरे में संशोधित कर चुके हैं। सांसद ने द्वीपसमूह में नौकरियों से संबंधित चुनौतियों को देखते हुए आयु सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है।

<><><><><><><><>

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति कोलकाता, उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच द्वारा तेरह दिसम्बर को सुबह दस बजे से कलकत्ता उच्च न्यायालय परिसर श्री विजयपुरम के सर्किट बेंच में दो हजार पच्चीस की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा ताकि कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित मामलों का निपटारा किया जा सके। जिसमें उच्च न्यायालय श्री विजयपुरम में कलकत्ता उच्च न्यायालय के सर्किट बेंच के समक्ष दायर किए जाने वाले संभावित मुकदमे पूर्व मामले भी शामिल हैं और इसमें पक्षकारों के बीच ए डी आर तंत्र के माध्यम से निपटारा किया जा सके। सभी इच्छुक संबंधितों से कहा गया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष अपने मामलों को निपटाने के लिए पक्षकारों और उनके अधिवक्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत आवेदन नौ दिसम्बर शाम पांच बजे एच सी एल एस सी के कार्यालय कलकत्ता उच्च न्यायालय परिसर श्री वियपुरम के सर्किट बेंच में स्वीकार किए जाएंगे।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से प्राप्त निर्देशों और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के नियम 18(1)(म) के अनुसार, परिवहन श्रेणी के ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए फॉर्म 5 A जमा करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी आवश्यकता उन परिवहन लाइसेंसों के पुनः सत्यापन के लिए है जिनकी समय सीमा समाप्त होने को है। यह 20 नवंबर से प्रभावी हो गया है। बिना फॉर्म 5 A के जमा किए गए किसी भी नवीनीकरण या पुनः सत्यापन के आवेदन को अधूरा माना जाएगा, और ऐसे आवेदनों की प्रक्रिया तब तक रोक दी जाएगी जब तक कि दस्तावेज जमा नहीं कर दिया जाता। जिन आवेदकों ने अपने आवेदन पहले ही जमा कर दिए हैं उनके आवेदन वापस किए जा सकते हैं ताकि वे फॉर्म 5 A अपलोड कर सकें। सभी परिवहन चालकों और अन्य हितधारकों से अनुरोध है कि वे इस बदलाव पर ध्यान दें और किसी भी देरी से बचने के लिए अपने नवीनीकरण आवेदन के साथ फॉर्म 5 A जमा करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, आवेदक परिवहन विभाग से संपर्क कर सकते हैं या निकटतम एसटीएस इकाइयों में जा सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर कल ब्लॉक परियोजना कार्यालय, लिटल अंडमान ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए 'समग्र शिक्षा' की समावेशी शिक्षा पहल के तहत एक 'खेल और एक्सपोजर विजिट' कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसमें लिटल अंडमान के विभिन्न स्कूलों के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। छात्रों के साथ उनके संबंधित एस्कोर्ट शिक्षक और अभिभावक भी उपस्थित थे, जिन्होंने पूरे आयोजन के दौरान बच्चों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग सुनिश्चित किया। बच्चों के बीच भागीदारी, आत्मविश्वास निर्माण और सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की समावेशी खेल गतिविधियाँ आयोजित की गईं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समावेशी प्रथाओं को बढ़ावा देना और सभी बच्चों, विशेष रूप से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना था। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की भागीदारी ने इस कार्यक्रम को सभी के लिए एक यादगार अनुभव बना दिया।

प्रशासन के कला एवं संस्कृति विभाग ने भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ई जेड सी सी कोलकाता की कार्यक्रम समिति के सदस्य के रूप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लोक या आदिवासी कला के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के नामांकन के लिए इच्छुक कलाकारों से आवेदन आमंत्रित किया है। इच्छुक कलाकार अपनी उपलब्धियों के विवरण के साथ अपना बायो-डाटा अटठारह दिसंबर तक सेल्युलर जेल परिसर स्थित कला एवं संस्कृति निदेशक के कार्यालय में जमा करने को कहा गया है।